सत्यमेव जयते

असंशोधित

14 JUL 1992

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बि०स०मु० (एल०ए०) 745—मोनो—500—19-2-1991—स०न०ल० मु

टर्न-10 बी./14-7-92
ब्र.

अल्प सूचित प्रश्न सं0: - ख-37

श्री रमेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं ।

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल (मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न योजना एवं विकास विभाग से स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

श्री रमेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय...

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल (मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का स्वरूप आप देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि यह प्रश्न योजना एवं विकास विभाग से संबंधित है क्योंकि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि रॉयल्टी से कितनी आमदनी होती है उसका एक परसेंट भी इन जिलों में विकास में खर्च नहीं होता है, तो विकास की यह राशि योजना और विकास विभाग देता है, न कि खनन विभाग । खनन विभाग का इतना ही काम है रॉयल्टी वसूल करना । हम रॉयल्टी वसूल करके फंड में जमा कर देते हैं और विकास के लिए किस जिले में कितना पैसा दिया जाएगा, यह योजना और विकास विभाग करता है, इसीलिए यह प्रश्न योजना एवं विकास विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

श्री रमेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मेरा आप सुन लीजिए । यह प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त विभाग से पूछा था । यह प्रश्न कृपया देखा जाए, "ख" को । क्या लिखा हुआ है ? यह वित्त विभाग से स्थानान्तरित करके खनन विभाग को भेजा गया है। यदि मंत्रीजी का कहना है कि योजना विभाग इसका जवाब देगा तो वित्त विभाग को योजना विभाग को भेजना चाहिए था, वित्त विभाग ने इसे खनन एवं भूतत्व को भेज दिया और माननीय मंत्री कहते हैं कि हमने योजना विभाग को भेज दिया, योजना कहेगा कि हम राजस्व को भेज दिए, इसीलिए यह मामला खनन विभाग से संबंधित है क्योंकि कोयले से जो वसूली होती है वह खनन विभाग ही वसूल करके जमा करता है, इसीलिए मूल प्रश्न खनन विभाग से है कि क्या कोयल से रॉयल्टी मद से आपको सालाना सात सौ करोड़ रूपये की आमदनी होती है या नहीं और यदि होती है तो संबंधित जिला को सरकार कितनी राशि विकास कार्य में देना चाहती है ?

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल (मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का दो भाग है । एक भाग है कि जितने जिलों का नाम माननीय सदस्य ने दिया है उसमें रॉयल्टी के मद में कितनी राशि प्राप्त होती है, सात सौ करोड़ रूपया इन्होंने बताया है, तो वित्त विभाग ने हमारे यहां प्रश्न भेज दिया, इसने कितनी राशि प्राप्त होती है, यह लिख कर योजना एवं विकास विभाग को भेज दिया है और योजना एवं विकास विभाग इनको एक परसेंट दे, दो परसेंट दे या आधा परसेंट दे, इसमें हमको कुछ नहीं कहना है ।

श्री महेन्द्र प्र०सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जवाब दें कि रॉयल्टी से इनको कित राशि प्राप्त होती है ? प्रश्न कर्त्ता ने जो राशि पूछी है वह सही है या नहीं, तो जवाब दें ?

अध्यक्ष: यह प्रश्न इन्होंने योजना विभाग को भेज दिया और योजना को जो भेजा, उसमें उन्होंने यह लिखा कि कितनी धन-राशि प्राप्त हुई हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा, रांची, और पलामू जिलों से ।

अब अगले दिन योजना विभाग इसका उत्तर देंगे ।

अल्प सूचित प्रश्न सं0: 38

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री ब्रजमोहन राय... श्री ब्रजमोहन राम...

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0: क. 500

श्री सुशील कुमार मोदी: अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ।

माननीय सदस्यों से एक आग्रह करना चाहता हूं । आप सवाल तो पूरा पूछ ही देते हैं तो किसी अखबार के खबर की कटिंग को शामिल करने की क्या जरूरत है । आपने तो क्वेश्चन पूरा पूछ ही दिया है ।

श्री राजो सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम जो प्रश्न पूछते हैं तो उसका आधार क्या है वह आपका ऑफिस मांगता है । आप अपने ऑफिस को कहिये कि वह कतरन नहीं मांगे ।

श्री राम जतन सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, जो पेपर कटिंग लगा कर देते हैं उसको तो जरूर स्वीकार कर लिये जाते हैं, हालांकि उसको अस्वीकार होना चाहिए ।

अध्यक्ष: पेपर कटिंग की जरूरत नहीं है । हम समझते हैं विभाग को तो मालूम रहता ही है ।

श्री चन्द्र मोहन राय: अध्यक्ष महोदय, पेपर कटिंग नहीं लगाने पर मेरा प्रश्न काट दिया गया है ।

श्री पीताम्बर पासवान(मंत्री): 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है । इन तीनों प्रमंडलों के पलामू एवं गढ़वा जिलों को छोड़ कर शेष जिले में सैचेट में देशी शराब आपूरित करने की प्रथा लागू कर दी गयी है । अपवारस्वरूप कुछ मामले प्रकाश में आए हैं